

भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

पराशोत्तम दास

(2023 की सिविल अपील संख्या 447)

21 मार्च, 2023

[संजय किशन कौल, बी. वी. नागरत्ता

और अभय एस. ओकेए, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 226 - तीन सशस्त्र बलों के सदस्यों से संबंधित सेवा मामले-क्या सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश अनुच्छेद के तहत रिट अधिकार क्षेत्र में चुनौती देने के लिए उत्तरदायी होगा। 226 किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान का-आयोजित: मेजर जनरल श्री कांत शर्मा और ए. एन. आर. में निर्णय। मामला सही कानून को निर्धारित नहीं करता है और एल. चंद्र कुमार मामले, एस. एन. मुखर्जी मामले और रोजर मैथ्यू मामले सहित इससे पहले और बाद में दिए गए संविधान पीठों के निर्णयों के विपरीत है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कला के तहत शक्ति के प्रयोग पर कोई प्रति-प्रतिबंध नहीं है। 226 में से

उच्च न्यायालय द्वारा संविधान-हालांकि, के मामलों के संबंध में

स्व-अनुशासन, सिद्धांत पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं।

भारत का संविधान-कला। 226 और 227-के तहत स्पष्टीकरण-यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति संविधान का निषेध नहीं है, और संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण और नियंत्रण कुछ अलग हैं

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्तियां।

अपीलों और रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़ना: 1 . यह न्यायालय इसके महत्व से अवगत है

सशस्त्र बलों और अनुशासन स्तर द्वारा निभाई गई भूमिका इन सेवाओं की आवश्यकता है। इस प्रकार, अक्सर कई न्यायशास्त्र

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के निर्णयों में अन्य न्यायाधिकरणों के सिद्धांतों को शामिल नहीं किया जा सकता है। सशस्त्र बलों के अपने नियम और 16 प्रक्रियाएँ हैं, और यदि इसका उचित प्रयोग किया जाता है

सशस्त्र बलों के मानदंडों के अनुसार अधिकार क्षेत्र,

उच्च न्यायालय या यह न्यायालय हस्तक्षेप करने में चौकस रहा है

उसी के साथ, सशस्त्र बल द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व को ध्यान में रखते हुए। [पैरा 24] [611-एच; 612-बी]

2. यद्यपि यह न्यायालय उपरोक्त सिद्धांत से सहमत है, यह न्यायालय मेजर जनरल श्री कांत शर्मा और अन्न के मामले में टिप्पणियों की सराहना करने में असमर्थ है। , जिसने अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

संविधान, संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान को कमजोर करता है जो मूल संरचना का भी हिस्सा है। बुनियादी संरचना के सिद्धांतों ने समय की कसौटी का सामना किया है और कई न्यायिक घोषणाओं में एक अंतिम परीक्षा के रूप में जोर दिया गया है। यह कुछ ऐसा है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का आत्म-प्रतिबंध उच्च न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने से अलग है।

न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न निर्णय की न्यायिक रूप से समीक्षा करते हुए संविधान। [पैरा 25] [612-बी-डी]

3. की अवधारणा को पेश करने वाली विधायिका पर

323 ए या अनुच्छेद 323 बी, पीठ का स्पष्ट रूप से यह विचार था कि न्यायाधिकरणों के निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे, और 42 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रतिबंधित नहीं होंगे, जिसने उपरोक्त दो अनुच्छेदों को पेश किया था। इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, इसे मामले को शांत करना चाहिए था, और कम से कम सात न्यायाधीशों की कोई भी पीठ इस प्रस्ताव पर संदेह नहीं कर सकती थी। रोजर मैथ्यू मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ में टिप्पणियों की आवश्यकता सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के कारण वास्तव में उत्पन्न हुई मेजर जनरल श्री कांत शर्मा और अन्न में की गई टिप्पणियाँ। इस प्रकार, यह दोहराया और स्पष्ट किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति बाधित नहीं है, और संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्तियों से कुछ अलग हैं। [पैरा 26] [612-ई-जी; 613-ए] [2023] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. उच्च न्यायालय को किसी भी त्रुटि को सुधारने से मना करना जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पड़ सकता है, यहां तक कि अभ्यास में भी

अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र संवैधानिक योजना के खिलाफ होगा। पहली स्वतंत्र न्यायिक जांच केवल सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा की जाती है। यह कहने के लिए कि कुछ मामलों में, एक न्यायिक

जांच एक दूसरी अपील के बराबर होगी, इसे देखने का सही तरीका नहीं होगा। जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि

प्रशासनिक न्यायशास्त्र, कम से कम दो स्वतंत्र न्यायिक

जाँच से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास अपार अनुभव होता है। अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के किसी भी प्रयोग में,

उच्च न्यायालय इसके दायरे और प्रकृति के बारे में काफी जागरूक हैं।

अधिकारिता, जो बदले में मामले की प्रकृति पर निर्भर करेगी। [पैरा 28] [613-ई-जी] 5. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे से कुछ मामलों को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाव दिया गया था। एस. एन. मुखर्जी मामले में संविधान पीठ के फैसले में इसका उल्लेख किया गया था।

यह मामला कि न्यायालयों-मार्शल के संबंध में भी, उच्च न्यायालय एक निश्चित परिदृश्य में उचित राहत प्रदान कर सकता है जैसा कि उसमें परिकल्पना की गई है, अर्थात्, "यदि उक्त कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या यदि उक्त कार्यवाहियां किसी अधिकार क्षेत्र की त्रुटि या किसी अन्य कारण से ग्रस्त हैं।

अभिलेख के सामने स्पष्ट कानून की त्रुटि "। [पैरा 29] [613-जीएच; 614-ए-बी]

6. अदालतें ऐसे परिदृश्य को कैसे स्वीकार कर सकती हैं जहां उपरोक्त स्थिति में भी एक पक्ष को बिना उपचार के छोड़ दिया जाता है? इस न्यायालय के लिए इसके विपरीत कुछ कहना या एस. एन. मुखर्जी मामले में संविधान पीठ के फैसले में उल्लिखित उपरोक्त अवलोकन को प्रतिबंधित करना न तो कानूनी होगा और न ही उचित होगा। यह न्यायालय किसी भी अपवाद को बनाने के लिए अनिच्छुक होगा, जिसमें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा निकाले गए अपवाद भी शामिल हैं। उपरोक्त के रूप में मामले की प्रकृति की परवाह किए बिना, यदि संविधान के भाग III के तहत किसी मौलिक अधिकार से इनकार किया जाता है या रिकॉर्ड के सामने कोई अधिकार क्षेत्र की त्रुटि या त्रुटि स्पष्ट है, तो उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। वहाँ।

यह एक गलत धारणा प्रतीत होती है कि उच्च न्यायालय

साक्ष्य की सराहना करें, जिससे इसे दूसरी अपील आदि बना दिया जाए। इस न्यायालय का मानना है कि उच्च न्यायालय भारत और ओ. आर. एस. के प्रति काफी सचेत हैं।

वी. पराशोटम दास

जिन मापदंडों के भीतर अधिकारिता का प्रयोग किया जाना है, और वे सिद्धांत, बदले में, इस न्यायालय द्वारा पहले से ही प्रतिपादित किए गए हैं। [पैरा 30] [614-बी-ई]

7. इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मेजर जनरल श्री कांत शर्मा और अन्न मामले में निर्णय दिया गया है। मामला सही कानून को निर्धारित नहीं करता है और एल. चंद्र कुमार मामले, एस. एन. मुखर्जी मामले और रोजर मैथ्यू मामले सहित इससे पहले और बाद में दिए गए संविधान पीठों के फैसलों के विपरीत है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग पर कोई प्रति-प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, आत्म-अनुशासन के मामलों के संबंध में, सिद्धांत पहले से ही प्रतिपादित हैं। [पैरा 32] [614 एफ-जी; 615-ए]

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 3 एस. सी. सी. 261: [1997] 2 एससीआर 1186; एस. एन. मुखर्जी बनाम।

भारत संघ (1990) 4 एससीसी 594: [1990] 11 पूरका एस. सी. आर. 44; रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस। (2020) 6 एससीसी 1: [2019] 16 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वी पाल सिंह बेदी आदि। भारत संघ और अन्य (1982) 3 एस. सी. सी. 140 [1983] 1 एस. सी. आर. 393; केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य ए. आई. आर. 1973 एससी

1461 [1973] पूरका एस. सी. आर. 1-संदर्भित। भारत संघ ओआरएस। वी. मेजर जनरल श्री कांत शर्मा और अन्न। (2015) 6 एससीसी 773: [2015] 4 एससीआर 676-आयोजित

सही कानून नहीं।

मामला कानून संदर्भ

[1983] 1 एससीआर 393

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[1997] 2 एससीआर 1186

पीछा किया।

पैरा 4

[1973] पूरका एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[1990] 11 पूरक। एससीआर 44

पीछा किया।

पैरा 12

[2019] 16 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा 15

[2015] 4 एससीआर 676

सही कानून नहीं माना गया

13 [2023] 3 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 447

2023 .

2012 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 662 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 30.01.2013 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

के. परमेश्वर, सुश्री आरती गुप्ता, सुश्री कांति, मुकेश कुमार शर्मा, श्रीमती सीमा बेंगनी, पद्मेश मिश्रा, युवराज शर्मा, आनंद वेंकटरमानी, श्रीमती विजयलक्ष्मी वेंकटरमानी, विनायक मेहरोत्रा, सुश्री मानसी सूद, चितवन सिंघल, सुश्री सोनाली जैन, अभिषेक कुमार पांडे, रमन यादव, अरविंद कुमार शर्मा, सिद्धांत कोहली, निशंक त्रिपाठी, सुश्री तान्या अग्रवाल, अर्काज कुमार, सुश्री हर्षिता सुखीजा, सुश्री आशिमा गुप्ता, आकाश किशोर, मकेश कुमार मरोरिया,

सुश्री अर्चना पाठक दवे, राकेश दहिया, सत्यवान कुडालवाल, अक्षत जैन, श्रीकांत नीलप्पा तेरदल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की प्रस्तावना -

1. भारत संघ के तीन सशस्त्र बलों के सदस्यों के सेवा मामलों से संबंधित बड़ी संख्या में मामले लंबित थे।

[illegible]

केंद्र सरकार कम से कम एक न्यायिक व्यवस्था के लिए कदम उठाएगी

सेवा मामलों में समीक्षा, और 1992 में संसद की प्राक्कलन समिति ने अपनी 19 वीं रिपोर्ट में उतना ही चाहा।

2. इन सशस्त्र सेवाओं में न्याय के प्रशासन की तत्कालीन मौजूदा प्रणाली ने सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों के खिलाफ वैधानिक शिकायतों को प्रस्तुत करने और विभिन्न अधिकारियों के निष्कर्षों और सजा के खिलाफ पुष्टि से पहले और बाद की याचिकाओं को प्रस्तुत करने का प्रावधान किया।

1 (1982) 3 एससीसी 140।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. पराशोतम दास [संजय किशन कौल, जे।]

अदालतें-वैवाहिक। इस प्रकार, तीनों सेनाओं के सदस्यों के बीच विश्वास और विश्वास को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना की कल्पना की गई थी। कोर्ट मार्शल के फैसलों के खिलाफ कानून के बिंदुओं और तथ्यों पर न्यायिक अपील का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था।

जिसकी अनुपस्थिति के कारण इस न्यायालय से प्रतिकूल टिप्पणियां आई थीं। विधेयक के अंततः पारित होने पर, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007, (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) 15.06.2008 से प्रभावी हुआ और बाद में कुछ संशोधन देखे गए।

कानूनी दुविधा:

3. उक्त अधिनियम के लागू होने पर, इसके कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न मुद्दे सामने आए। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे सामने विचारणीय है क्या सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र में चुनौती देने के लिए उत्तरदायी होगा। इस मुद्दे की जरूरत है

हमारे सामने कई मामलों पर विचार और इस प्रस्ताव पर निर्णय के परिणामस्वरूप इन विभिन्न मामलों में कुछ परिणामी आदेश पारित किए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि प्रमुख मामले सहित कुछ मामलों में, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आपत्ति भी नहीं उठाई गई थी, हालांकि उस अभ्यास पर हमारे समक्ष हमला करने की मांग की गई है।

निजी पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ:

4. श्री अरविंद दातार, विद्वान वरिष्ठ वकील, और श्री के. परमेश्वर, विद्वान वकील, ने विभिन्न सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्तियों की ओर से दलीलों का नेतृत्व किया। वे दृढ़ता से

उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर कभी कोई रोक नहीं हो सकती है, हालांकि, कभी-कभी, उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करने का अपना विवेकाधिकार बनाता है। उन्होंने एल. चंद्र कुमार बनाम मामले में इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ पर भरोसा किया। भारत संघ और अन्य 2, जो

स्पष्ट रूप से राय दी कि अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना और न्यायाधिकरण के सभी निर्णयों का हिस्सा है, चाहे वह संविधान के अनुच्छेद 323 ए 3 या 323 बी4 के तहत गठित हो।

संविधान, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

2 (1997) 3 एससीसी 261। 3 323 ए। प्रशासनिक न्यायाधिकरण।

4 323 बी. अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. एल. चंद्र कुमार के मामले में चर्चा ने केरल के केशवानंद भारती के मौलिक मामले और उसके बाद के कई अन्य फैसलों में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। एल. चंद्र कुमार के पैरा 62 में चर्चा को इस रूप में निकालना 1 होगा

“ :

" 62. केशवानंद भारती मामले में तरह-तरह न्यायाधीशों का संविधान बेंच, 7 के बहुमत से: 6 , अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के आधार पर संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, कि

शक्ति का प्रयोग संविधान की बुनियादी विशेषताओं को नुकसान पहुँचाने या इसकी मूल संरचना को नष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। पहचान

विशेषताएँ जो हमारी मूल संरचना का गठन करती हैं संविधान भारतीय संवैधानिक कानून में बड़ी बहस का विषय रहा है। कठिनाई इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि बहुमत के निर्णय भी इस पहलू पर सर्वसम्मति से सहमत नहीं होते हैं। [बहुमत के लिए पाँच निर्णय थे,

सीकरी, सी. जे., शेलट एंड ग्रोवर, जे. जे. द्वारा वितरित। हेगड़े और मुखर्जी, जे. जे. जगनमोहन रेड्डी, जे. और खन्ना, जे. जबकि खन्ना, जे. ने बुनियादी विशेषताओं को सूचीबद्ध करने का प्रयास नहीं किया, जिनकी पहचान

अन्य न्यायाधीशों की बुनियादी विशेषताओं को न्यायालय के निर्णयों के निम्नलिखित पैरास में निर्दिष्ट किया गया है: सीकरी, सी. जे. (पैरा 292), शेलट और ग्रोवर, जे. जे.। (पैरा 582), हेगड़े और मुखर्जी, जे. जे.। (पैरा 632 और 661) और जे. जगमोहन रेड्डी (पैरा 1159,1161)]। न्यायिक समीक्षा के पहलू का सभी बहुमत निर्णयों में विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। तथापि, खन्ना, जे. ने इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से संबोधित किया।

(पैरा 1529 में):

.....हालाँकि, न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल यह तय करने तक ही सीमित नहीं है कि क्या विवादित कानूनों को बनाने में केंद्रीय या राज्य विधानमंडलों ने उनके लिए निर्धारित विधायी सूचियों के चार कोनों के भीतर काम किया है; अदालतें इस सवाल पर भी विचार करती हैं कि क्या कानून संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुरूप बनाए गए हैं और उनका उल्लंघन नहीं करते हैं। जब तक कुछ मौलिक अधिकार मौजूद हैं और संविधान का एक हिस्सा हैं, तब तक न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग इस दृष्टि से भी किया जाना चाहिए कि क्या गारंटी दी गई है।

उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। न्यायिक समीक्षा

अ)

1973 एससी 1461

अ)

भारत और ओआरएस का संघ। वी. पराशोतम दास [संजय किशन कौल, जे।]

इस प्रकार यह हमारी संवैधानिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गया है और कानूनों के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता के बारे में निर्णय लेने की शक्ति उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। यदि कानून के प्रावधान संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, जो सभी कानूनों की वैधता के लिए कसौटी है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को उक्त अनुच्छेद को रद्द करने का अधिकार है। प्रावधान "।

किसी भी व्यवहार्य वैकल्पिक अपील तंत्र की कमी के कारण। इस में मोड़, इस पर आधारित था: सबसे पहले, संविधान का अनुच्छेद 136 (2) उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए किसी भी विशेष अनुमति की अनुमति नहीं देता है।

सशस्त्र बलों से संबंधित किसी कानून द्वारा या उसके तहत गठित न्यायालय या न्यायाधिकरण का आदेश। दूसरा, उक्त अधिनियम की धारा 31 में कहा गया है कि इस न्यायालय में अपील केवल तभी होगी जब "सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून का एक बिंदु" शामिल हो।

7. इस प्रकार, चूंकि अधिकांश मामले सेवा मामलों की प्रकृति के होने के कारण वादियों के लिए व्यक्तिगत हैं, और इसमें "सामान्य सार्वजनिक महत्व" का कानून का कोई बिंदु शामिल नहीं हो सकता है, इसलिए एक वादी के पास अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को छोड़कर शिकायत निवारण के लिए कोई मंच नहीं है, जिससे वह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित होकर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा, विधानमंडल उक्त अधिनियम की धारा 14 का मसौदा तैयार करते समय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र की मौलिकता के प्रति सचेत था, जो स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अनुच्छेद 226 के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से उत्पन्न अपीलों पर विचार करने से बचाता है और

संविधान का अनुच्छेद 227।

8. उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) निम्नानुसार है।

" 14. सेवा मामलों में अधिकारिता, शक्तियाँ और अधिकार। - (1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित किए जाने के अलावा, न्यायाधिकरण नियत दिन को और उससे, उस दिन से तुरंत पहले प्रयोग करने योग्य सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकरण का प्रयोग करेगा।

(संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर)

सभी सेवा मामलों के लिए "।

9. विद्वान वकीलों ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 समान सामग्री में नहीं हैं और इस प्रकार, लागू की गई सीमा [2023] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 227 (4) के तहत संविधान के अनुच्छेद 226 तक विस्तार नहीं किया जा सका। अनुच्छेद 227 (4) "इस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं" वाक्यांश के साथ शुरू होता है जिसका अर्थ है कि प्रावधान में प्रतिबंध केवल उस अनुच्छेद तक ही सीमित है।

10. अनुच्छेद 227 (4) को पुनः प्रस्तुत करना सार्थक होगा, जो इस प्रकार है:

227. उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति

अदालत -

(4) इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी उच्च न्यायालय को किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां प्रदान करती नहीं मानी जाएगी।

सशस्त्र बलों से संबंधित किसी कानून द्वारा या उसके तहत गठित।

11. इस प्रकार, तर्क के लिए भी, यह कहा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 227 (4) उच्च न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति को छीन लेता है।

अदालतों से उत्पन्न होने वाले मामलों के लिए-उक्त अधिनियम की धारा 158 के तहत मार्शल, यह अदालतों से निपटने वाले मामलों के लिए भी अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम नहीं करेगा-मार्शल। किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत आदेशों के खिलाफ रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं, और दूसरी अपील का न्यायालय बनने से इनकार कर दिया है।

12. विद्वान वकीलों ने एस. एन. मुखर्जी बनाम में टिप्पणियों के आधार पर अपने तर्कों को मजबूत किया। भारत संघ ', विशेष रूप से अनुच्छेद 42, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालयों को, अनुच्छेद 226 के तहत, कोर्ट मार्शल के संबंध में भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है और उच्च न्यायालय उचित राहत दे सकते हैं "यदि उक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप मौलिक अधिकारों से इनकार किया गया है। संविधान के भाग III के तहत गारंटी या यदि उक्त कार्यवाही किसी अधिकार क्षेत्र की त्रुटि या रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट कानून की किसी त्रुटि से ग्रस्त है।

13. उपरोक्त संदर्भ में, यह आग्रह किया गया था कि भारत संघ में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की टिप्पणियाँ और

ओआरएस। वी. मेजर जनरल श्री कांत शर्मा और Anr.¹, इसके खिलाफ थे कानून का सुव्यवस्थित सिद्धांत और उसके बाद से स्थापित न्यायिक मिसाल

8 अदालत के खिलाफ अपील के मामलों में अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और अधिकार-मार्शल 9 (1990) 4 एस. सी. सी. 594

10 10 (2015) 6 एससीसी 773 भारत और ओआरएस का संघ।

वी. पराशोतम दास [संजय किशन कौल, जे।]

निर्णय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से उत्पन्न निर्णयों की समीक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इस तरह का एक पूर्ण बार इसके विपरीत है

एल. चंद्र कुमार 1 1 और एस. एन. मुखर्जी 1 2 में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय। क्या महत्वपूर्ण था, यह आग्रह किया गया था,

कि मेजर जनरल श्री कांत शर्मा और Anr.¹³ 13 में निर्णय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि किसी सेवा मामले में पीड़ित व्यक्ति को यदि उच्च न्यायालय का दरवाजा खटने से रोका जाता है, तो उसके पास सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क करने का कोई कानूनी सहारा नहीं रहेगा, क्योंकि सेवा मामले निजी प्रकृति के होते हैं और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 31 के तहत "सामान्य सार्वजनिक महत्व के कानून के बिंदु" शामिल नहीं होते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 136 (2)। 14. इस प्रकार, इस दृष्टिकोण को एल. चंद्र कुमार 1 में सात न्यायाधीशों की पीठ की टिप्पणियों के साथ सीधे टकराव में कहा गया था।

पैरा 79, जो निम्नानुसार है:

" 79. हम यह भी मानते हैं कि उच्च न्यायालयों में अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर न्यायिक पर्यवेक्षण का प्रयोग करने की शक्ति भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थिति जिसमें उच्च न्यायालयों को संवैधानिक व्याख्या के अलावा अन्य सभी न्यायिक कार्यों से वंचित कर दिया जाता है, समान रूप से

टाल दिया "।

15. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि हाल ही में पांच-न्यायाधीशों की पीठ के संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए मुद्दे अब एकीकृत नहीं हैं।

रोजर मैथ्यू बनाम में इस न्यायालय का। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और Ors.¹⁵ जहां अनुच्छेद 215 में, एल. चंद्र कुमार के बाद, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र शक्ति को सीमित नहीं करता है।

सैन्य या सशस्त्र बलों के विवाद के खिलाफ उच्च न्यायालय का, स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से और यह कि अनुच्छेद 227 (4) के तहत प्रतिबंध केवल उच्च न्यायालयों द्वारा प्रशासनिक पर्यवेक्षण के लिए है न कि न्यायिक समीक्षा के लिए। पैरा 215 इस प्रकार है:

11 (उपर्युक्त) एल 12 13 ((उपर्युक्त)) 14 (उपर्युक्त) 15 (2020) 6 एस. सी. सी. 1

16 (ऊपर)

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियों को सीमित नहीं किया गया है सैन्य या सशस्त्र बलों के खिलाफ स्पष्ट रूप से या निहितार्थ द्वारा

विवाद। अनुच्छेद 227 (4) द्वारा किया गया सीमित निष्कासन केवल काम करता है।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक पर्यवेक्षण और न्यायिक नहीं

समीक्षा करें। अनुच्छेद 136 (2) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सीधी अपील को प्रतिबंधित करता है।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरणों के एक आदेश से न्यायालय, लेकिन नहीं

न्यायिक समीक्षा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील को प्रतिबंधित करें

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया। भारत संघ और सशस्त्र बलों की जे. ए. जी. शाखा की दलीलें

बल

16. श्री संजय जैन और कर्नल बालासुब्रमण्यम ने विरोध करने की कोशिश की

उक्त अधिनियम की धारा 3 (ओ) की पहली छमाही के लिए उत्तरदायी है

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण और विज्ञापन में सूचीबद्ध मामले सशस्त्र बलों के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

नल। धारा 3 (ओ) निम्नानुसार है:

" 3. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो आवश्यकता है,

.....

.....

.....

सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) का अर्थ है संबंधित सभी मामले।

उनकी सेवा की शर्तों के लिए और शामिल होंगे

((i) पारिश्रमिक (भत्तों सहित), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ;

((ii) कमीशन, नियुक्ति, नामांकन सहित कार्यकाल,

परिवीक्षा, पुष्टि, वरिष्ठता, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वापसी, समय से पहले सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, सेवा की समाप्ति और दंडात्मक कटौती;

((ग) संक्षिप्त निपटान और विचारण जहाँ -

बर्खास्तगी प्रदान की जाती है;
मामला, जो भी हो,

((iv) कोई अन्य

लेकिन इसमें भारत संघ और ओ. आर. एस. से संबंधित मामले शामिल नहीं होंगे।

वी. पराशोतम दास [संजय किशन कौल, जे।]

(i) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 18, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 15 की उप-धारा (1) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 18 के तहत जारी आदेश; और

(सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) और वायु सेना अधिनियम के अधीन व्यक्तियों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से या इकाई, गठन या जहाज के एक भाग के रूप में पोस्टिंग पर स्थान या इकाई के परिवर्तन सहित स्थानांतरण और पोस्टिंग।

1950 (45 1950)।

((ग) किसी भी प्रकार की छुट्टी।

((iv) सारांश कोर्ट मार्शल, सिवाय इसके कि जहां सजा की जाए।

तीन महीने से अधिक के लिए बर्खास्तगी या कारावास;

17. उक्त धारा 30 और 31 की अपीलों से निपटने के लिए अध्याय 5 के तहत धारा 30 और 31 के तहत अपीलीय तंत्र भी प्रदान किया गया है।

" 30. सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। - (1) विषय के अधीन धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार, न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय या आदेश (धारा 19 के तहत पारित आदेश के अलावा) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जाएगी:

बशर्ते कि ऐसी अपील की अवधि के भीतर वरीयता दी जाती है

उक्त निर्णय या आदेश के नब्बे दिन:

बशर्ते कि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी

न्यायाधिकरण का अंतर्वर्ती आदेश। (2) न्यायाधिकरण के किसी भी आदेश या निर्णय के अधिकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपील की जाएगी।

अवमानना के लिए दंड देना:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत एक अपील आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाएगी।

इसके खिलाफ अपील की।

(3) उप-धारा (2) के तहत किसी भी अपील को लंबित रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय

आदेश दे सकते हैं कि

(क) दंड या अपील किए गए आदेश का निष्पादन।

निलंबित किए जाने के विरुद्ध; या

(ख) यदि अपीलार्थी कारावास में है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाए:

23] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि जहां कोई अपीलकर्ता न्यायाधिकरण को संतुष्ट करता है कि वह अपील करने का इरादा रखता है, वहां न्यायाधिकरण, यथास्थिति, खंड (ए) या खंड (बी) के तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

31. अपील करने के लिए छोड़ दें। - (1) उच्चतम न्यायालय में एक अपील न्यायाधिकरण की अनुमति के साथ होगी और ऐसी अनुमति नहीं होगी यह तब तक दिया जाता है जब तक कि यह न्यायाधिकरण द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है कि निर्णय में सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून का कोई बिंदु शामिल है, या ऐसा प्रतीत होता है

उच्चतम न्यायालय के लिए कि मुद्दा वह है जो होना चाहिए

उस न्यायालय द्वारा विचार किया गया।

(2) सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए न्यायाधिकरण को एक आवेदन न्यायाधिकरण के निर्णय की तारीख से शुरू होने वाले तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा और न्यायाधिकरण को एक आवेदन दिया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय छुट्टी के लिए उस तारीख से शुरू होने वाली तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा जिस दिन छुट्टी के लिए आवेदन किया जाता है।

न्यायाधिकरण ने अस्वीकार कर दिया।

(3) अपील को तब तक लंबित माना जाएगा जब तक कि अपील करने की अनुमति के लिए किसी भी आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है और यदि अपील करने की अनुमति दी जाती है, जब तक कि अपील का निपटारा नहीं किया जाता है और अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन को उस समय की समाप्ति पर निपटाया गया माना जाएगा जिसके भीतर यह किया जा सकता था, लेकिन यह उस समय के भीतर नहीं किया गया है।

18. हमें यहाँ यह इंगित करना चाहिए कि धारा 30 को पढ़ने से पता चलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान निम्नलिखित के अधीन है -

धारा 31 के प्रावधान। धारा 31 के तहत ऐसी अपील सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की अनुमति के साथ होगी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ऐसी अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि वह यह प्रमाणित नहीं करता है कि निर्णय में सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून का कोई बिंदु शामिल है, या सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह बिंदु वह है जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है।

19. इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपील तंत्र चरित्र में प्रतिबंधात्मक है, कुछ ऐसा जो सरकारी वकीलों को नहीं मिल सका

से दूर। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने आग्रह किया कि यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा, तो यह अभ्यास चरित्र में प्रतिबंधात्मक होना चाहिए।

भारत और ओ. आर. एस. की धारा 30 और 31 संघ। वी. पराशोतम दास [संजय किशन कौल, जे।]

उक्त अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 136 (2) ने भी अपील की अनुमति पर विचार करते हुए इस तरह का प्रतिबंध लगाया है।

20. विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय से प्रतिबंध लगाने की मांग की निम्नलिखित में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना मामले:

कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी, कोर्ट ऑफ मार्शल से संबंधित सभी मामले और

(i)

अनुशासन;

(ii) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, कार्यकाल, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, प्रशासनिक समाप्ति से संबंधित सभी मामले।

सेवा, जैसे कि नैतिक अधमता से जुड़े मामलों में, और छुट्टी;

(ग) सरकारी गोपनीयता अधिनियम से संबंधित मामले; और

(iv) जासूसी/तोड़फोड़ से संबंधित मामले।

21. निवेदन यह था कि अदालतों सहित सभी अनुशासनात्मक मामले

मार्शल, जो साक्ष्य के पुनः मूल्यांकन को अनिवार्य कर सकता है, को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। यही दूसरी आपराधिक अपील के बराबर हो सकती है।

22. एक अतिरिक्त दलील दी गई कि वर्तमान में कुछ नहीं कहा गया है।

निर्णय को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कमजोर करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो बरकरार रहेगा। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र में मामलों की एक निश्चित श्रेणी के निर्णय के संबंध में अवलोकन केवल न्याय के सुचारू प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए था।

23. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो सामान्य से अलग है।

अनुच्छेद 323 ए के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण या संविधान के अनुच्छेद 323 बी के तहत अन्य न्यायाधिकरण और इस प्रकार, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेशों में नियमित रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 226 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समान अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का प्रयास करना।

हमारी टिप्पणियाँ:

24. हमने विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा जोर दिए गए अंतिम पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार किया है।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के महत्व के साथ, और इसका अधिकार क्षेत्र अन्य न्यायाधिकरणों से अलग है। हम सशस्त्र बलों द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व और इन सेवाओं के लिए आवश्यक अनुशासन स्तर के प्रति सचेत हैं। इस प्रकार, अक्सर कई न्यायशास्त्र के सिद्धांत [2023] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बल न्यायाधिकरण। सशस्त्र बलों के अपने नियम और प्रक्रियाएँ हैं, और यदि सशस्त्र बलों के मानदंडों के अनुसार अधिकार क्षेत्र का उचित प्रयोग होता है, तो उच्च न्यायालय या यह न्यायालय सशस्त्र बलों द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसमें हस्तक्षेप करने में सावधानी बरतता है।

25. यद्यपि हम उपरोक्त सिद्धांत से सहमत हैं, हम मेजर जनरल श्री कांत के मामले में टिप्पणियों की सराहना करने में असमर्थ हैं।

शर्मा & Anr.¹⁷ 17, जिसने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान को कमजोर कर दिया जो मूल संरचना का भी हिस्सा है। बुनियादी संरचना के सिद्धांतों ने समय की कसौटी का सामना किया है और कई न्यायिक घोषणाओं में एक अंतिम परीक्षा के रूप में जोर दिया गया है। यह है।

ऐसा कुछ नहीं जिस पर संदेह किया जा सके। यह स्थिति होने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का आत्म-प्रतिबंध न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न निर्णय की न्यायिक रूप से समीक्षा करते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में उच्च न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने से अलग है।

26. विधायिका द्वारा "न्यायाधिकरण" की अवधारणा को पेश करने पर (कोई यह कह सकता है कि इस अवधारणा ने विभिन्न न्यायाधिकरणों की तुलना में कई सवालिया निशान देखे हैं, हालांकि इसने कुछ सफलताएं भी हासिल की हैं), इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एल. चंद्र कुमार के मामले में इसका परीक्षण किया गया था। इस प्रकार, के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए

उपरोक्त दो अनुच्छेदों को प्रस्तुत किया। हमारे विचार में, इससे मामला शांत हो जाना चाहिए था और सात से कम न्यायाधीशों की कोई भी पीठ ऐसा नहीं कर सकती थी प्रस्ताव पर संदेह किया। रोजर मैथ्यू मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ में टिप्पणियों की आवश्यकता वास्तव में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के लिए आवश्यक है।

मेजर जनरल श्री कांत शर्मा में की गई टिप्पणियों के कारण उत्पन्न हुआ और इस प्रकार, यह दोहराया और स्पष्ट किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति बाधित नहीं है, और

18 (ऊपर)

19 (ऊपर)

20 (ऊपर)

भारत और ओआरएस का संघ। वी. पराशोतम दास [संजय किशन कौल, जे।]

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्तियों से कुछ अलग हैं।

27. हम निजी पक्षों के तर्क में भी योग्यता पाते हैं कि

विभिन्न सशस्त्र बलों पर लागू नियमों में परिकल्पित प्रशासनिक/अनुशासनात्मक निर्णय के खिलाफ न्यायाधिकरण द्वारा एकल न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 31 निस्संदेह रूप से प्रतिबंधात्मक है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में अपील केवल सामान्य सार्वजनिक महत्व के कानून के एक बिंदु पर होगी। विद्वान वकीलों के आग्रह के अनुसार, ऐसे कई मुद्दे हैं जो सामने आए हैं, जो व्यक्तिगत हैं और बड़े सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। 28. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के निर्माण से पहले अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इन मामलों को संभालने के कुछ अनुभव के साथ हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में पेंशन के मामले हुआ करते थे। जिन व्यक्तियों ने सशस्त्र बलों में सेवा की थी, उन्हें पेंशन के चरण में छोड़ दिया गया था। यह अधिकार क्षेत्र भी सशस्त्र के पास निहित है

बल न्यायाधिकरण। यह कहना मुश्किल होगा कि पेंशन के मामले में एक बड़ा जनहित शामिल होगा, लेकिन फिर, उस संबंधित व्यक्ति के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय को किसी भी त्रुटि को सुधारने से मना करना, जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में भी पड़ सकता है, संवैधानिक योजना के खिलाफ होगा। पहली स्वतंत्र न्यायिक जांच केवल सशस्त्र बलों द्वारा की जाती है

न्यायाधिकरण। यह कहना कि कुछ मामलों में न्यायिक जांच दूसरी अपील के बराबर होगी, इसे देखने का सही तरीका नहीं होगा। ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रशासनिक न्यायशास्त्र में, हमारे विचार में, कम से कम दो स्वतंत्र न्यायिक जांचों से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास अपार अनुभव होता है। अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के किसी भी प्रयोग में, उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र के दायरे और प्रकृति के बारे में काफी सचेत हैं, जो बदले में अधिकार क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

बात है। 29. हमारा मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे से कुछ मामलों को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

संविधान, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाव दिया गया था। एस. एन. में संविधान पीठ के फैसले में इसका उल्लेख किया गया था। 21 (ऊपर)

23] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुखर्जी 22 मामला है कि अदालतों के संबंध में भी-मार्शल, उच्च न्यायालय एक निश्चित परिदृश्य में उचित राहत दे सकता है जैसा कि उसमें परिकल्पना की गई है, अर्थात्, "यदि उक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप इनकार किया गया है

संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार

या यदि उक्त कार्यवाही किसी क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि या किसी अन्य समस्या से ग्रस्त है। अभिलेख के सामने स्पष्ट कानून की त्रुटि "।

यदि संविधान के भाग III के तहत किसी मौलिक अधिकार से इनकार किया जाता है या रिकॉर्ड के सामने कोई अधिकार क्षेत्र की त्रुटि या त्रुटि स्पष्ट है, तो उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गलत धारणा कि उच्च न्यायालय साक्ष्य की पुनः सराहना करेगा, जिससे इसे दूसरी अपील आदि बना दिया जाएगा। हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय उन मापदंडों के प्रति काफी सचेत हैं जिनके भीतर अधिकार क्षेत्र है।

प्रयोग किया जाना है, और वे सिद्धांत, बदले में, इस न्यायालय द्वारा पहले से ही प्रतिपादित किए गए हैं।

31. हम यह भी समझने में विफल हैं कि वर्तमान निर्णय में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर अधिनियम या संवैधानिक योजना के तहत परिकल्पित सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कमजोर करने की कोई आशंका क्यों होनी चाहिए।

निष्कर्ष:

32. इस प्रकार, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मेजर जनरल श्री कांत शर्मा और Anr.24 मामले में निर्णय निर्धारित नहीं है।

सही कानून और एल. चंद्र कुमार 25 मामले, एस. एन. मुखर्जी मामले और रोजर मैथ्यू 27 मामले सहित इससे पहले और बाद में दिए गए संविधान पीठों के निर्णयों के विपरीत है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके प्रयोग पर कोई प्रति-प्रतिबंध नहीं है।

22 (ऊपर)

23 (ऊपर)

24 (ऊपर)

25 (ऊपर)

26 (ऊपर)

27 (ऊपर)

भारत और ओआरएस का संघ। वी. पराशोतम दास [संजय किशन कौल, जे।]

आर उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। हालांकि, आत्म-अनुशासन के मामलों का दृष्टिकोण, सिद्धांत पहले से ही खड़े हैं

सियेटेड।

33. हम अब सामान्य प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं,

आदर्श मामले क्योंकि उन्हें आदेशों की अलग प्रकृति की आवश्यकता हो सकती है। वास्तव में,

जिन मामलों और अनुरोध किए गए आदेशों की प्रकृति को भी विद्वान वकील श्री के. परमेश्वर द्वारा निर्धारित किया गया है और उनसे निपटा जा रहा है। कमियाँ:

I. मामलों की पहली श्रेणी वह है जहाँ मामले थे।

संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों द्वारा गुण-दोष पर सुनवाई लेकिन निर्णय को देखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं होने के रूप में निपटाया गया था

मेजर जनरल श्री कांत शर्मा और Anr.28 मामले में। ये

आम जनता के लिए कानून के मुद्दों को उठाने वाले मामले नहीं हैं

महत्व और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर जांच की जानी चाहिए। इस प्रकार, इन मामलों को संबंधित उच्च न्यायालय को भेजे जाने की आवश्यकता है

योग्यता पर निर्णय के लिए अदालतें। मामले की संख्या और दलों के नाम इस प्रकार हैं:

आई.

एसएलपी (सी) No.20721/2015 शीर्षक दक्षिण कुमारी बनाम। संघ
भारत से।

ii.

एसएलपी (सी) No.17320/2017 शीर्षक के. सी. शिवू बनाम। संघ का
भारत।

एसएलपी (सी) No.20499/2015 शीर्षक कृष्ण नंदन मिश्रा

iii.

वी. भारत संघ।

एसएलपी (सी) No.26617/2015 शीर्षक नंद लाल वर्मा बनाम। संघ

iv.

भारत से।

एसएलपी (सी) No.26568/2015 शीर्षक रणदीप सिंह गुलेरिया

वी.

वी. भारत संघ।

एसएलपी (सी) No.26620/2015 शीर्षक गोपी राम बनाम। संघ का

vi.

भारत।

एसएलपी (सी) No.36386/2015 शीर्षक अवि चंदर सूद बनाम। संघ

vii.

भारत से।

रा)

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

आई. एसएलपी (सी) No.5111/2016 शीर्षक गुरचरण सिंह बनाम। भारत संघ; एसएलपी (सी) No.28101/2016 शीर्षक निर्मल सिंह बनाम।

भारत संघ।

एसएलपी (सी) No.1788/2023 शीर्षक देविंदर सिंह बनाम। संघ

भारत से।

एसएलपी (सी) No.34797/2014 शीर्षक भारत संघ बनाम। परशोतम दास, जिसे भारत संघ द्वारा योग्यता के आधार पर दायर किया गया था

राहत देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती

उत्तरदाता को। इस मामले पर गुण-दोष के आधार पर इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। सिविल अपील में भारत संघ No.5327/2015 शीर्षक भारत संघ बनाम। थॉमस वैद्यन एम. ने एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की मांग की कि क्या कोई चुनौती सीधे इस न्यायालय को दी जाएगी या केवल उच्च न्यायालय के समक्ष। चूंकि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिकाओं को विचारणीय माना जाता है, इसलिए यह मामला

योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय में भेजे जाने की भी आवश्यकता होगी क्योंकि यह एक व्यक्तिगत सेवा का मामला है

वादी और इसमें सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून का कोई बिंदु शामिल नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 31 और 32 के अधिकारों को डब्ल्यू. पी. (सी) No.76/2016 में चुनौती दी गई थी जिसका शीर्षक गुरबक्स सिंह ढिंडसा बनाम था। भारत संघ, एक वायु सेना अधिकारी के पिता द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर किया गया था, जो जम्मू-कश्मीर में एक परिचालन क्षेत्र में मारे गए थे। वह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राहत पर ब्याज का दावा कर रहा था लेकिन नहीं कर सका

एक सीधी अपील दायर की है क्योंकि मामला वादी के लिए व्यक्तिगत था और इसमें सामान्य कानून का कोई बिंदु शामिल नहीं था

सार्वजनिक महत्व और उच्च न्यायालय मनोरंजक नहीं थे।

यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 30 घोषित करने के लिए प्रार्थना & 31 क्योंकि रिट के मामले में अल्ट्रा वायर्स नहीं दबाया जाएगा

अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र को बनाए रखने योग्य माना जाता है और इस प्रकार, इस मामले को भारत और ओ. आर. एस. संघ की स्वतंत्रता के साथ निपटाने की प्रार्थना की गई थी।

वी. पराशोतम दास [संजय किशन

कौल, जे।]

उच्च न्यायालय का रुख

करें। हम याचिका और आदेश ए को स्वीकार करते हैं

तदनुसार।

34. जितने बड़े सवाल का जवाब

दिया जा चुका है, उपरोक्त

प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, हमारे द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत मामलों से निपटा जाएगा।

35. अपीलों और रिट याचिकाओं का निपटारा

उपरोक्त शर्तों में किया जाता है, जिससे पक्षकारों को अपना खर्च खुद वहन करना पड़ता है।

अंकित ज्ञान

(सहायक: आरश चौधरी, एलसीआरए)